राजपत्र

The Gazette of

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section I प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77 1

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2001/फाल्गुन 28, 1922

No. 77] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2001/PHALGUNA 28, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2001

विषय:- नेपाल से जिंक आक्साइड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना।

सं. 7/1/2001-श्रीजीएडी.—मैं. ट्रांसपेक इंडस्ट्रीज लि., बड़ौदा और में. डेमोशा कैमिकल्स लि. मुम्बई ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षिति निर्धारण) नियम 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक याचिका दायर की है, जिसमे नेपाल से (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) से जिक आक्साइड के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा पाटनरोधी जांच करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

- 2. <u>घरेलू उद्योग की स्थिति</u>ः यह याचिका मैं0 ट्रांसपेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैं0 डेसोशा कैमिकल्स लि0, जिनके पंजीकृत कार्यालय क्रमशः कलाली रोख, अटलाडरा रोड, बड़ौदरा गुजरात और 105ए, मित्तल टावर्स, 210, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021 में स्थित है, के द्वारा दायर की गइ है। याचिकाकर्ताओं का देश में जिंक आक्साइड के घरेलू उत्पादन में बड़ा हिस्सा है। इस प्रकार याचिकाकर्त्ता नियम 5(क) और (ख), तथा नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की और से याचिका दायर करने की स्थिति में है।
- 3. शामिल उत्पादः- वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से नियार्तित जिंक आक्साइड (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) है, और जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 2817.0001 के अन्तर्गत वर्गीकृत है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।
- 4. शामिल देश:- याचिकाकर्ता ने नेपाल (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) से जिंम आक्साइड के पाटपन का आरोप लगाया है।
- 5. समान वस्तुएं- याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु और जो सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 2817.0001 के अन्तर्गत वर्गीकृत है, का कोई विकल्प नहीं है और यह तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से नेपाल से आयातित वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापनीय है, इसलिए इसे नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान वस्तु के रूप में माना जाता है।
- 6. सामान्य मूल्यः- सामान्य मूल्य का परिकलन संबद्ध देश के लिए समुचित समायोजन के साथ याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन लागत के आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

- 7. निर्यात कीमतः- याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (५.डीजीसीआई एण्ड एस) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकडों के आधार पर नियात कीमत का दावा किया है । संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत निकालने के लिए कमीशन, समुद्री भाड़े, लदान प्रभार और बीमा के संबंध में उचित समायोजनों पर विचार किया गया है ।
- 8. <u>पाटन मार्जिनः</u> इस बात के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य उस मूल्य से काफी अधिक है जिस पर इसे भारत को निर्यात किया गया है, जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।
- 9. **क्षति:-** पाटित आयातों के कारण कीमत में कटौती,स्थिर मांग के बावजूद कीमतों में कमी के कारण वित्तीय घाटा, जैसे क्षति से संबंधित विभिन्न मापदण्डों से सामूहिक एवं संचयी रूप से प्रथम दृष्ट्या यह पता चलता है कि संबद्ध देश से हुए पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- 10. पाटनरोधी जांच की शुरूआत:- उपरोक्त पैराग्राफों को ध्यान में रख्वाते हुए प्राधिकारी, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।
- 11. जांच अवधि:- वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1.4.99 से 30.09.2000 तक की है।
- 12. सूधना प्रस्तुत करना:- उक्त देश में निर्यातकों और भारत में संबंधित ज्ञात आयातों को

अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढ़ंग से संगत सूचना निम्नलिखित पते पर भेजें तथा अपने विचारों से अवगत कराएं-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन.

नई दिल्ली-110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी निर्धारित ढंग से तथा निर्धारित प्रपत्र में जांच से संबंधित अपने अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकती है:

- 13. समय सीमा: वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । तथापि जिन ज्ञान निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी
- 14. सभी पार्टियां पाटनरोधी नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय आधार पर उपलब्ध की गई किसी सूचना के अगोपनीय अंश को उपलब्ध कराएंगी । तथापि, कृपया यह नोट किया जाय कि इस प्रकार की सूचना पाटनरोधी नियम 7(1) और 7(2) के अनुसार स्वीकार की जाएगी।
- 15. नियम 6(7) के अनुसार, कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के बाद कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए है।
- 16. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाधा डालती हैं तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधर पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिश कर सकते हैं।

एल.वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRFCTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2001

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of Zinc Oxide from Nepal.

No. 7/1/2001-DGAD .-- M/s. Transpek Industries Ltd., Baroda and M/s. Demosha Chemicals Limited,

Mumbai have filed a petition, on behalf of the domestic industry, in accordance with the customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on dumped articles and for determination of duty) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Zinc Oxide from Nepal (herein referred to as subject country) and have requested for Anti-Dumping investigation and levy of Anti-Dumping duties.

- 2. <u>Domestic industry standing</u>: The petition has been filed by M/s Transpek Industries Ltd. and M/s Demosha Chemicals Ltd. having registered offices at Kalali Road, Atladra Road, Vadodara, Gujarat and 105A, Mittal Towers, 210, Nariman Point, Mumbai-400021 respectively. The petitioners account for a major proportion of the domestic production of Zinc Oxide in the country. Therefore, the petitioners satisfy the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per Rule 5(a) and (b) and Rule 2 (b).
- 3. <u>Product involved</u>: The product involved in the present investigation is Zinc Oxide (herein referred to as subject goods), originating in or exported from the subject country and classified under Customs Sub-heading 2817.0001 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
- 4. <u>Countries involved</u>: The petitioner has alleged dumping of Zinc Oxide from Nepal (herein referred to as subject country).
- 5. <u>Like articles:</u> The petitioner has claimed that the goods produced by them and as classified by Custom Tariff under head 2817.0001 have no substitute and are technically and commercially substitutable with the goods imported from Nepal and, therefore, be treated as like articles to the goods imported from the subject country within the meaning of the Rules.
- Normal value: The normal value has been constructed on the basis of the cost of production data provided by the petitioner with appropriate adjustments for the subject country.

- 7. Export Price: The petitioner has claimed Export price based on data provided by Directorate General of Commercial Intelligence and Supplies (DGCI&S). Appropriate adjustments on commission, freight, loading charges and insurance have been considered to evaluate the ex-factory export price of the subject goods from the subject country.
- 8. <u>Dumping margin</u>: There is sufficient prima-facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the price at which it has been exported to India indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject country.
- 9. <u>Injury</u>: Various parameters relating to injury such as price undercutting by the dumped imports, financial losses due to depressed prices despite stable demand, prima-facie collectively and cumulatively indicate that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping from subject country.
- 10. <u>Initiation of Anti-Dumping Investigation</u>: The authority in view of the foregoing paragraphs initiates anti-dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country.
- 11. <u>Period of investigation</u>: The period of investigation for the purpose of present investigation is 1.4.99 to 30.9.2000.
- 12. <u>Submission of information</u>: The exporters in the said country and importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and make their views known to:-

The Designated Authority
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Udyog Bhavan
New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

13. <u>Time limit:</u> Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers who are being addressed separately are however, required to submit the information within 40 days from the date of letter addressed to them separately.

- 14. All parties must provide a non-confidential summary of any information provided on a confidential basis in terms of Anti-Dumping Rule 7(2). Please, however, note that such information will be subject to acceptance in terms of Anti-Dumping Rule 7(1) and 7(2).
- 15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties after expiry of time limits set.
- 16. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority